बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 199 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 08 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली विधानसभा में बनी फांसी घर पर विवाद! आखिर क्या है ये मामला, जिस पर हो रहा है हंगामा?

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में इन दिनों एक नए मुद्दे पर बहस और बवाल देखने को मिली है. विधानसभा सत्र के दौरान परिसर में फांसी घर के अवशेषों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए दावे अब विवादों में घिर गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (6 अगस्त) को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस कथित 'फांसी घर' के जीर्णोद्धार पर खर्च हुए एक-एक रुपये की वसूली होनी चाहिए, क्योंकि यह जनता को गुमराह करने की कोशिश थी. दरअसल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा परिसर में एक कक्ष का उद्घाटन 'फांसी घर' के रूप में किया था. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे 'टिफिन रूम' बताया, जो ब्रिटिश काल में 'इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' का हिस्सा था.

अदालत में जस्टिस यशवंत वर्मा की अपील खारिज, जली नकदी मामले में जांच प्रक्रिया को दी थी चुनौती

नई दिल्ली।

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत की पीठ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा, वह असंवैधानिक नहीं था। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल की उस रिपोर्ट को अमान्य ठहराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी मामले में दोषी पाया गया था। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि जांच समिति की रिपोर्ट और उसे राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेजना असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया। बता दें कि ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से नकद राशि मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने एक इन-हाउस जांच समिति बनाई थी। इस समिति ने जांच के बाद जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मामले में जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि जांच

में उन्हें ठीक से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि साबित करने की जिम्मेदारी समिति पर होनी चाहिए थी, उनसे सफाई मांगना गलत था। उनका दावा था कि निष्कर्ष पहले से तय थे और जल्दीबाजी में जांच की गई। इसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनकी मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है, तो वे वहां अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सीजेआई सिर्फ डाकघर नहीं हैं, बल्कि उनके पास अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी है। मामले में कोर्ट ने कहा कि कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई। समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजना संविधान के खिलाफ नहीं है। पीठ ने ये भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश सिर्फ नाम का पद नहीं होता, उनके पास देश और न्यायपालिका के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। वे केवल एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दो टूक कहा कि जस्टिस वर्मा का व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप नहीं है और उनके खिलाफ की गई जांच और कार्रवाई सही थी। बात अगर मामले में जांच की करें तो जांच पैनल ने पाया कि नोट्स एक ऐसे स्टोअर रूम में पाए गए थे, जो केवल न्यायाधीश के आवास का हिस्सा था और उसमें उनकी या उनके परिवार की पूरी तरह से पहुंच थी। पैनल ने इस घटना को गंभीर मानते हुए अध्यक्षता में ट्रांसफर से बढ़कर कार्रवाई की सिफारिश की, और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजी गई। गौरतलब है कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब फरवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने पर, उन्हें सरकारी कर्मचारी और दमकल आग बुझाने आए थे। इस दौरान वहां एक कमरे में बहुत बड़ी मात्रा में जला हुआ या आधा जला हुआ नोट पाया गया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की। साथ ही, इन-हाउस इन्वेस्टिगेशन (अंदरूनी जांच) शुरू करने का निर्णय लिया गया।

सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन, कहा- इनके बचपन की रक्षा हमारा संकल्प

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने जनसुनवाई कार्यालय में छोटे-छोटे बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, बच्चियों से कलाई पर राखी बंधवाई और इन छोटे-छोटे बच्चों को गिफ्ट और मिठाई दी. साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चों के साथ 1 घंटे बातचीत की और उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी हासिल की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा, आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सिर्फ रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना एक रिश्ता बांधा गया और एक संकल्प फिर से दोहराया गया कि हम इनके बचपन की रक्षा करेंगे, इनके सपनों की रखवाली करेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, बच्चे दिल्ली के भविष्य हैं और उस भविष्य की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित जनसुनवाई कार्यालय में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा बच्चों के बीच बैठीं, उनसे बातचीत की, बच्चों के साथ रक्षाबंधन के अपने अनुभव साझा किए और बच्चों से उनकी पढ़ाई-लिखाई और स्कूल की व्यवस्था के बारे में भी जाना. साथ ही, बच्चों के साथ आई उनकी टीचर्स से भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बातचीत कर स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था पर जानकारी ली.

इसके अलावा, बच्चियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनकी तस्वीर गिफ्ट में दी. तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को गिफ्ट में स्कूल बैग, टेडी बियर और मिठाइयां देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार न सिर्फ बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है, बल्कि उनके विकास के लिए भी लगातार काम कर रही है. इस समय चल रहे दिल्ली विधानसभा के मानसून सेशन में रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रण करने का बिल लाई है, जिससे न सिर्फ हर साल बढ़ी फीस का भार अभिभावकों के ऊपर से हटेगा, बल्कि बिल में यह भी नियम रखा गया है कि अगर कोई स्कूल फीस की वजह से बच्चे को प्रताड़ित करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.

स्वतंत्रता दिवस समारोह से कुछ दिन पहले लाल किले पर तलाशी में दो कारतूस बरामद, फ़ोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक एक हफ़्ते पहले नई दिल्ली के लाल किले में की गई तलाशी के दौरान दो पुराने कारतूस बरामद हुए हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों कारतूस क्षतिग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं और उन्हें फ़ोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा, एक सर्किट बोर्ड भी मिला है, जो पुराना प्रतीत होता है। आशंका है कि इस बोर्ड का इस्तेमाल किसी पुराने कार्यक्रम के दौरान लाइटिंग सेटअप में किया गया होगा।

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच जारी है। एएनआई द्वारा उद्धृत अधिकारियों के अनुसार, लाल किले पर नियमित सुरक्षा अभ्यास के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सहित सात दिल्ली पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस अभ्यास के दौरान, विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम ने परिसर में एक नकली बम लगाया था। हालाँकि, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी इसे पकड़ नहीं पाए,

जिसके कारण तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली पुलिस नियमित रूप से इस तरह का अभ्यास करती है। हाल ही में किए गए निलंबन का उद्देश्य उच्च सुरक्षा वाले इस अवसर से पहले कड़ी सतर्कता सुनिश्चित करना था। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पाँच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। सभी आरोपी अवैध प्रवासी हैं और राष्ट्रीय राजधानी में मज़दूरी करते रहे हैं। इन सभी की उम्र लगभग 20-25 वर्ष है। पुलिस ने उनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज़ बरामद किए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा! खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी

नई दिल्ली । चालू मानसून सीजन और लगातार बारिश के बीच, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह 7 बजे 204.79 मीटर तक बढ़ गया, जो 204.50 मीटर के चेतावनी निशान को पार कर गया और इस मौसम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जलस्तर में यह वृद्धि चालू मानसून सीजन के दौरान लगातार बारिश के बीच हुई है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव हो गया है। लगातार बारिश ने नदियों के जलस्तर को खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंचा दिया है। सुबह 8 बजे, पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर था, जो नदी के प्रवाह और बाढ़ के खतरे की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली में, यमुना का चेतावनी स्तर 204.5 मीटर है, खतरे का निशान 205.3 मीटर है, और नदी का जलस्तर 206 मीटर तक पहुँचते ही निकासी के प्रयास शुरू हो जाते हैं। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि मुख्यतः हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण हुई है।

इस मानसून सीज़न में पहली बार बैराज से पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक को पार कर गया, जो सुबह 6 बजे के आसपास 61,000 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। तब से, हर घंटे लगभग 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुँचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जलभराव और नालों के उफान के कारण दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं, वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी के तुलसी घाट के ऊपर बाढ़ का पानी पहुँच गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए, गंगा नदी में चलने वाली सभी नावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, शनिवार को नदी का जलस्तर 69.98 मीटर था, जो वाराणसी में 71.26 मीटर के खतरे के निशान के बेहद करीब है। ऋषिकेश में, लगातार भारी बारिश के कारण परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, और आश्रम के आरती स्थल पर भगवान शिव की मूर्ति तक पानी पहुँच गया है।

दिव्यांगजनों के लिए भी फुटपाथ जरूरी, अदालत ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया

नई दिल्ली ।

देश के सभी नागरिकों, विशेषकर दिव्यांगों और बुजुर्गों को सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह चार हफ्तों के भीतर ऐसे दिशा-निर्देश बनाए, जो देशभर में सभी फुटपाथों को सुलभ और अतिक्रमणमुक्त बनाएं। यह आदेश डॉक्टर एस. राजासेकरन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने भारत के फुटपाथों की दयनीय स्थिति और दिव्यांगजनों की परेशानियों को उजागर किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि देश में कई जगह फुटपाथ हैं ही नहीं, और जहां हैं वहां या तो टूटे-फूटे हैं या अतिक्रमण के शिकार हैं। इससे न सिर्फ दिव्यांगों की आवाजाही मुश्किल होती है बल्कि आम पैदल यात्रियों की जान भी खतरे में रहती है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए दलील दी गई कि हर नागरिक को समानता और जीवन का अधिकार है, जिसमें सुरक्षित चलना भी शामिल है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि अभी तक इस विषय पर कोई ठोस राष्ट्रीय दिशा-निर्देश नहीं हैं।

इसलिए केंद्र सरकार को तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियम बनाने होंगे। पहला, सभी नई और पुरानी सड़कों पर तकनीकी मानकों के साथ फुटपाथ की अनिवार्यता तय करना। दूसरा, डिजाइन ऐसा हो कि दिव्यांगजनों को कहीं भी दिक्कत न हो। तीसरा, अतिक्रमण को हटाने और रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर केंद्र सरकार तय समय में गाइडलाइन नहीं बनाती है, तो अदालत खुद अमिकस क्यूरी (अदालत के मित्र) की मदद से दिशानिर्देश तैयार करेगी। इसके साथ ही रायों को छूट दी गई है कि वे या तो इन राष्ट्रीय गाइडलाइनों को अपनाएं या अपनी गाइडलाइंस बनाएं, लेकिन मानक एक जैसे होने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करे। अगली सुनवाई एक सितंबर 2025 को होगी, जिसमें केंद्र और रायों की जवाबदेही की समीक्षा की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश ने दिव्यांगों और पैदल यात्रियों के अधिकारों को मजबूती से सामने रखा है।

ट्रम्प की स्ट्राइक और हमारे नेतृत्व की परीक्षा

मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वह अपनी डैड इकॉनमी को मिल कर गिरा सकते है, भारत पर 25फीसदी टैरिफ थोपते हुए अमेरिका के असंतुलित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के यह कड़वे शब्द बहुत देर चुभते रहेंगे और इनमें भारत और अमेरिका के रिश्ते को तबाह करने की पूरी क्षमता है। ऐसे कहा जा रहा है कि जैसे हम नार्थ कोरिया हों। सामरिक विशेषज्ञ ब्रैंक ग्रासमैन के अनुसार, मई 1998 के बाद यह भारत और अमेरिका की सामरिक पार्टनरशिप के लिए सबसे बुरा दिन है। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है और दोनों मिल कर पाकिस्तान के विशाल तेल रिज़र्व का विकास करेंगे। पाकिस्तान के साथ समझौते की घोषणा हमें चिढ़ाने के लिए की गई है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के कथित तेल रिज़र्व के बारे कोई हलचल नहीं है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया सावधानीपूर्वक और परिपक्व रही है। कहा गया कि हम राष्ट्रीय हित में निर्णय लेंगे और रूस से रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इन शब्दों के साथ भारत ने ट्रम्प की धौंस का संयमित जवाब देने की कोशिश की है, पर समस्या तो है। आखिर अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके साथ बिगड़ते रिश्ते हमारे हित में नहीं हो सकते। नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का बहुत प्रयास किया है। याद रखिए अब की बार ट्रम्प सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति का रवैया भारत विरोधी है। जिस पाकिस्तान को उनसे पहले राष्ट्रपति अछूत समझते रहे उसे ही ट्रम्प साथी बनाने में लगे हैं। वह देश जिसे दुनिया आतंकवाद का अड्डा जानती है और जो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय भिखारी है, वह कूटनीति में हमें मात कैसे दे गया? दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन जो हमारी तरफ झुका हुआ था, को ट्रम्प उलटाने में लगे हैं। ट्रम्प के बदले रुख का कारण क्या है? एक कारण है कि भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का श्रेय देने को तैयार नहीं। ट्रम्प लगभग दर्जन बार कह चुके हैं कि युद्ध विराम उन्होंने करवाया जबकि भारत सरकार का कहना है कि युद्ध विराम तब हुआ जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इसकी याचना की। पाकिस्तान उसका श्रेय ट्रम्प को दे रहा है और उन्हें नोबेल सम्मान देने की सिफारिश कर चुका है जो अहंकारी ट्रम्प को बहुत पसंद आई है जबकि भारत का कोरा जवाब था कि नोबेल पुरस्कार की बात व्हाइट हाउस में ही करें। पाकिस्तान में हमारे पूर्व राजदूत गौतम बम्बावाला ने माना है कि ट्रम्प की ईगो को खुश कर पाकिस्तान ने 'अपने पत्ते सही चले हैं'। हर्ष पंत जोऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में विशेषज्ञ है, का कहना है कि ट्रम्प इसलिए नाराज है क्योंकि भारत के साथ ट्रेड डील किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार भी राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी सारी ट्रेड टीम 'भारत के साथ ट्रेड वार्ता को लेकर हताश है। भारत वह पहला देश था जिसने अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता शुरू की थी। शुरू में हमने टैरिफ घटा कर ट्रम्प को खुश करने के लिए कई रियायतें भी दी थीं। हम वहां से आयात, जिसमें रक्षा सामान भी शामिल है, वह बढ़ाने जा रहे हैं। इसी के कारण ट्रम्प भारत और मोदी को 'फ्रैंड' कहते रहे हैं, पर अब 25% टैरिफ लगा दिया है और हमारी अर्थव्यवस्था को 'डैड' करार दिया। तीसरा बड़ा कारण है कि हम कृषि और डेयरी क्षेत्र को उनके लिए खोलने को तैयार नहीं हैं। हम उन्हें इस क्षेत्र में एंट्री नहीं दे सकते जिस पर हमारी जनसंख्या 65 प्रतिशत लोग निर्भर हैं। अमेरिका में हर किसान को वार्षिक 26 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है जबकि हमारे एक किसान की औसत आय एक लाख रुपए से कम है। हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। ट्रम्प की नाराज़गी का अगला कारण रूस है। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रम्प का दावा था कि बनने के बाद वह 24 घंटों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा देंगे। पर यह हो नहीं रहा क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। रूस पर दबाव डालने के लिए ट्रम्प हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम रूस से तेल लेना बंद कर दें और रक्षा सामान की खरीद कम कर दें। अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी कई बार भारत और चीन पर आरोप लगा चुके हैं कि हम रूस से जो तेल और रक्षा सामान खरीदते हैं उससे यूक्रेन के खिलाफ रूस की युद्ध मशीनरी के लिए धन मिलता है। चीन क्योंकि बराबर की टक्कर दे सकता है इसलिए उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पर हमें जुर्माना लगाने की भी ट्रम्प ने धमकी दी है। रूस के तेल पर हमारी निर्भरता यूक्रेन युद्ध से पहले 2% से बढ़ कर जून 2024 में 40% हो गई थी। उनका तेल सस्ता है और हमारा अधिकतर रक्षा सामान रूस से आता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी सफल रही है, भी रूस के साथ पार्टनरशिप में यहां बनती है।

हम रूस से अलग हो नहीं सकते, और न ही अमेरिका जैसे अविश्वसनीय देश के पाले में जा सकते हैं। हमारी लीडरशिप के लिए यह न केवल बड़ी चुनौती है बल्कि परीक्षा भी है। लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि वह निक्सन के आगे डटी रहीं। इस सरकार की यह भी समस्या है कि यह प्रदर्शित करते रहे कि मोदी और ट्रम्प बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है उसने देश का बहुत अहित किया है। जो मोदी और ट्रम्प के बीच 'केमिस्ट्री' को लेकर गद्गद् हो रहे थे उन्होंने देश को गुमराह किया है। लोकराय बिल्कुल अमेरिका विरोधी हो चुकी है क्योंकि लोग समझते हैं कि हमसे विश्वासघात हुआ है। अगर सरकार कुछ समझौता करने की कोशिश भी करेगी उसे लोग समर्पण समझेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प की सोच में केवल लाभ का महत्व है, न सद्भावना का है, न किसी गठबंधन का है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अचानक हमारे लिए अप्रिय हो गया है। हमारा कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। हमारे विकल्प सीमित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसी देश ने हमें ऑपरेशन सिंदूर से नहीं रोका, पर यह भी कड़वी सच्चाई है कि किसी देश ने खुल कर हमारा समर्थन नहीं किया और न ही पाकिस्तान की निंदा ही की है। हमारे छोटे-छोटे पड़ोसी देश भी तमाशा देखते रहे। एक तरफ चीन सीमा पर फुंकार रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के भी सब खून माफ कर दिए गए हैं। अमेरिका का कुल घाटा 1200 अरब डॉलर है जिसमें हमारा योगदान केवल 40 अरब डॉलर का है।

अर्थात इस टैरिफ-स्ट्राइक का सम्बंध केवल अर्थव्यवस्था से ही नहीं है। यह सामरिक और राजनीतिक स्ट्राइक भी है। दबाव के नीचे झुकना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। ट्रम्प हमारी आर्थिक, विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता समाप्त करना चाहते हैं। ब्राज़ील, कैनेडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने झुकने से इंकार कर दिया है। रूस से हमें अलग करने का अशिष्ट प्रयास हमारी सामरिक प्रतिष्ठा पर चोट है। जैसे डॉ.मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने लिखा है '1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान को लेकर अमेरिका और चीन एक ही तरफ हैं'। यह अधिक देर नहीं रहेगा क्योंकि चीन जिसने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है चुपचाप अमेरिका और पाकिस्तान में बढ़ती घनिष्ठता बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अब अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी और दूसरे बाजार ढूंढने पड़ेंगे। यह आसान नहीं होगा। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने लिखा है, ट्रम्प के प्रतिशोध करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है, पर हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि बंदूक की नोक पर समझौता नहीं हो सकता, न होगा। नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनौती ही नहीं अपना नेतृत्व और मजबूत करने का मौका भी है। अंत में भारत को अपमानित करने के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने हमें डैड इकॉनमी कहा है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी 4 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था हैं और कुछ महीनों में हम जापान को पछाड़ कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे लेकिन ट्रम्प साहिब को हमारी अर्थव्यवस्था मुर्दा नजर आती है। एनडीटीवी ने कई अमेरिकी एआई सिस्टम से सवाल किया कि 'क्या भारत की अर्थव्यवस्था डैड है?' जवाब बड़े दिलचस्प है।

ट्रंप की धमकी बनाम राष्ट्रीय हित सर्वोपरि,भारत फर्स्ट् की नीति

वैश्विक स्तरपर आज दुनियाँ का हर देश ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद से उनके द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों व व्यवहार से सख्ती में है व सोचने के लिए मजबूर है कि, वह क्या करें? क्योंकि ट्रंप चुनावी वादों अमेरिका फर्स्ट,व मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए वित्त के विभिन्न स्रोतों का जुगाड़ कर रहे है, वह भी एक नए अंदाज में, टैरिफ का दबाव बनाकर। उन देशों को अपनी शर्तों, मांगों को मानने पर विवश कर रहे हैं, यह हमने देखे कि चीन पर 145 परसेंट तो कनाडा और पूरे यूरोपीय यूनियन तक सभी देशों में टैरिफ के माध्यम से दबाव का का खेला खेलने को हम देख रहे है,अब 1 अगस्त से भारत पर 25 परसेंट टैरिफ की घोषणा, फिर उसे संशोधन कर 7 अगस्त तक बढ़ाया जाना, फिर आज मंगलवार 5 अगस्त 2025 को देर शाम उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल लेकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध में वित्तीय फंडिंग के रूप में मदद कर रहा है,उसे रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। अमेरिका अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ा देगा।मैं एडवोकेट किशन सनमुख दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं, चूंकि वह दिन अब लग गए जब भारत पर दबाव बनाकर उसके अटल इरादों को डगमगा दिया जाता था,अब भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि वह अपनी मर्जी, अपने दम व अपनी शर्तों पर राष्ट्रहित सर्वोपरि पर काम करेगा, यानें मेक इन इंडिया व विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रहित में रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। बता दें ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन व अमेरिकी फर्स्ट् की नीति पर चल रहे है, जो उनके चुनावी वादे का एक हिस्सा है।अब भारत अमेरिका दोनों देश अपने राष्ट्र को ग्रेट बनाना चाहते है, जो अच्छी बात है। परंतु इसके लिए दबाव नीति रूपी अस्त्र का उपयोग करना उचित मानदंडों के खिलाफ है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे अमेरिका व यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंधों के बावजूद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा खरीद रहे है, तो भारत के साथ ऐसा प्रस्ताव क्यों? साथियों बात अगर हम ट्रंप की धमकी को ऊर्जा,राजनीति व दबाव की रणनीतिक कड़ी के रूप में देखें तो, ट्रंप की धमकी और अमेरिका का वास्तविक रुख-डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई और 5 अगस्त 2025 को दो बार भारत को धमकाया कि यदि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो अमेरिका भारत पर 24 घंटे के भीतर बहुत बड़े टैरिफ लगा देगा। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वहसस्ता तेल रूस से खरीदता है, उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है,और इस प्रकार युद्ध को फंड कर रहा है लेकिन इस कथन में दो प्रमुख विरोधाभास है (1) संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है। (2) अमेरिका ने यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बड़े समझौते किए है जो रूस की जगह लेने के नाम पर खुद लाभ कमा रहे है।भारत पर अमेरिका की तेल नीति और शुल्क धमकी-डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई और 4-5 अगस्त 2025 को दोहराकर स्पष्ट किया कि भारत की रूस से तेल खरीद को वह युद्ध मशीन को ईंधन देना मानते है, और इस वजह से भारत से आयात पर 25पेर्सेंट से कहीं अधिक बहुत बड़ी टैरिफ वृद्धि करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकरडिस्काउंट पर और फिर उसे ओपन मार्किट में मुनाफे के लिए बेचता है,रोइटर्स और इंडिया टाइम्स सहित रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी-जून 2025 में भारत की कुल तेल खपत का लगभग 36-40 पेर्सेंट हिस्सा रूस से आया था अमेरिका और यूरोप स्वयं कितना तेल खरीद रहे है? यूरोपीय संघ यूरोस्टाट के आंकड़ों के अनुसार अर्ली 2025 तक ईयू ने पेट्रोलियम ऑयल आयात में मार्च-2021 की तुलना में मूल्य में 956 पेर्सेंट वृद्धि, मात्रा में थोड़ा 9+0.3

पेर्सेंट बढ़ोतरी दर्ज की-हालांकि 2022 के बाद क्रमशः दोनों में गिरावट आई है।2024 में ईयू ने अमेरिका से करीब ब76 बिलियन मूल्य एलएनजी, पेट्रोलियम और कोयला आयात किया-कुल यूएस ऊर्जा निर्यात . 318 बिलियन में से ईयू का हिस्सा लगभग 24 पेर्सेंट था। यूरोप को आपूर्ति में यूएस का हिस्सा 2024 में एलएनजी में 944पेर्सेंट, तेल में 915.4 पेर्सेंट था अमेरिका- -अमेरिका ने 2024 में रोजाना औसतन 4.1 मिलियन बैरल/दिन क्रूड ऑयल निर्यात किया – 2023 से नए रिकॉर्ड को पार करते हुए यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा रॉ डिलीवरी नीदरलैंड को (लगभग 8.25 लाख ब/दिन), फिर जर्मनी, यूके आदि को हुई। उसी वर्ष भारत को अमेरिका की क्रूड ऑयल निर्यात में 32 पेर्सेंट की वृद्धि हुई- रूस से सस्ता तेल मिलने पर भी, भारत यूएस. क्रूड को भरपूर स्थान दे रहा है लगभग 55,000 बैरल/दिन की बढ़ोतरी।

साथियों बात अगर हम ट्रंप द्वारा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रश्न खड़ा करने की करें तो,ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में (5-6 अगस्त 2025 तक) भारत पर आयात टैरिफ बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते है, वर्तमान में 25 पेर्सेंट के स्थान पर 50 पेर्सेंट, 100 पेर्सेंट, या उससे भी ज्यादा तक। यूएस. कांग्रेस में सैंक्शनिंग रूस एक्ट ऑफ 2025 प्रस्तावित है, जिसमें ऐसे देशों पर 500 पेर्सेंट सेकेंडरी टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है जो रूसी ऊर्जा आयात करते है (विशेष रूप से भारत, चीन) यह बिल लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथाल द्वारा लाया गया है और समर्थन प्राप्त कर रहा है।द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक प्रभाव यह तनाव, केवल तेल-सम्बंधित नहीं-भारत और यूएस के बीच व्यापार और विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिसमें कृषि और रक्षा संबंध शामिल है रेटिंग एजेंसीयों नेअनुमान लगाया कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स से भारत को . 7-18 बिलियन वार्षिक नुकसान हो सकता है, और जीडीपी वृद्धि रेट में मामूली गिरावट (90.2 पेर्सेंट) आ सकती है जबकि तेल और ऊर्जा लागत में .11बिलियन तक का इजाफा हो सकता है।लेकिन भारत की नई उद्यमशील (स्टार्टअप्स) और बुनियादी व्यापारिक भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है-उन्होंने भविष्य के लिए भारत में निवेश बकौनी माना है। संयुक्त दृष्टिकोण अमेरिका और ईयू-जहाँ खुद ब्लॉक को रूसी ऊर्जा आयात से दूर करने की योजना चल रही है-वह सीमित दायरे में भारत पर ही कठोर है।

यह विश्व राजनीति में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रश्न खड़े करता है। ऊर्जा नीति-भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविध स्रोतों से तेल प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, हालांकि यूएस. से निर्यात बढ़ना एक अवसर है लेकिन वो रूस से प्राप्त सस्ते स्रोत की जगह तुरंत नहीं ले सकते। राजनीतिक संतुलन-ट्रंप प्रशासन का रुख, हालांकि चाइना, पाकिस्तान को भी थोड़ा अलग तरीके से देखा-दिल्ली को मुश्किल चुनाव करना होगा- या ट्रंप की मांगों को स्वीकार किया जाए और रिश्तों को बनाए रखा जाए,या रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए आर्थिक- पॉलिटिकल रुख अपनाया जाए। अतः अगर हम उपलब्ध पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप की धमकी बनाम राष्ट्रीय हित सर्वोपरि,भारत फर्स्ट् की नीति,भारत के लिए चुनौती- अमेरिका के आगे झुकना नहीं, संबंध तोड़ना नहीं, सम्मान को छोड़ना नहीं,अमेरिका व यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंधों के बावजूद प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा खरीद रहे है तो भारत के साथ ऐसा बर्ताव क्यों?

सम्पादकीय...

मालेगांव विस्फोट फ़ैसला: जुर्म तो हुआ, लेकिन कोई सज़ा नहीं

2008 के मालेगांव बम धमाको पर बहुप्रतीक्षित फ़ैसला मुंबई की एक विशेष अदालत ने सुनाया। इस फ़ैसले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह फ़ैसला जहां पीड़ितों के लिए एक झटका था, वहीं हिंदुत्व खेमे में इसे लेकर जश्न मनाया गया। दरअसल, बहुत से लोगों को इस तरह के फ़ैसले की पहले से ही आशंका थी और उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं रही, क्योंकि पिछले 17 वर्षों में जांच एजेंसियों की दिशा विशेष रूप से 2014 के बाद बदलती गई। मालेगांव धमाका एक ऐसे समूह ने किया था जो मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहा था। इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था और विस्फोट उस समय हुआ जब रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ वहां मौजूद थी। धमाके में छह लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए। जिन सात लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें भोपाल की पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल थे। शुरुआत में मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज़्म स्क्वाड ने की थी, लेकिन 2011 में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। फ़ैसले में अदालत ने कहा कि आरोपियों की संलिप्तता को लेकर गंभीर संदेह ज़रूर है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसलिए सभी को बरी किया जा रहा है। इस फ़ैसले का दक्षिणपंथी हिंदू खेमे ने स्वागत किया और साथ ही कांग्रेस पर भगवा आतंक की कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। मालेगांव विस्फोट की जांच के कुछ अहम पहलुओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस मामले की जांच करने वाले एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने इसकी शुरुआत प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल से की थी। प्रज्ञा ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थीं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है। जांच इन्हीं आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 2006 में नांदेड़ में भी एक विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट राजकोंडवार नामक व्यक्ति के घर में हुआ जब बम बनाते समय गलती से वह फट गया। इस घटना की नागरिक जांच समिति ने, जिसमें पूर्व राष्ट्र सेवा दल अध्यक्ष सुरेश खैरनार भी शामिल थे, जांच की थी। इसमें हिमांशु पांसे (27) और नरेश राजकोंडवार (26) की मौत हो गई, जबकि योगेश देशपांडे, मारुति वाघ और गुरुराज तुप्तेवार गंभीर रूप से घायल हुए। घटनास्थल पर बजरंग दल का झंडा लहराता मिला और नकली दाढ़ी-मूंछ और पायजामा-कुर्ता भी बरामद हुए। जब करकरे मालेगांव धमाके की गंभीर जांच कर रहे थे, तब शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, हम करकरे पर थूकते हैं क्योंकि वह हिंदुओं के खिलाफ़ कार्य कर रहे हैं। भाजपा के नेता और उस समय विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन टिप्पणियों से आहत करकरे ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और ईमानदार अफ़सर जूलियो रिबेरो से संपर्क किया। रिबेरो ने उनके काम की सराहना की और उन्हें पेशेवर ढंग से जांच जारी रखने की सलाह दी। 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में करकरे शहीद हुए। इसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक करोड़ रुपये का चेक लेकर उनकी विधवा को देने पहुँचे, जिसे उन्होंने विनम्रता से ठुकरा दिया। वहीं मोदी, जो पहले करकरे पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते थे क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था, अब उन्हें शहीद बता रहे थे।

करकरे की दुखद मृत्यु के बाद, प्रज्ञा ठाकुर ने इस घटना को लेकर अपनी एक अलग कहानी पेश की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ भाजपा के कई नेता उन्हें घेरे खड़े थे और समर्थन दे रहे थे, ठाकुर ने करकरे को राष्ट्रविरोधी और धर्मविरोधी कहा। उन्होंने कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उससे कहा था – 'तेरा सर्वनाश होगा'। और ठीक सवा महीने बाद, आतंकवादियों ने उसे मार डाला। अजमेर, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस धमाकों में स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 CrPC के तहत अपने अपराध स्वीकार किए थे। यह बयान दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में 18 दिसंबर को दिया गया, और न्यायिक हिरासत में 48 घंटे रखने के बाद दर्ज किया गया ताकि किसी भी दबाव की आशंका न रहे। असीमानंद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने और अन्य हिंदू कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर बम का जवाब बम से देने की रणनीति अपनाई। बाद में उन्होंने यह बयान वापस ले लिया और कहा कि यह जबरन लिया गया था। लेकिन पुलिस के सामने नहीं बल्कि जज के सामने दिए गए बयान को ऐसे वापस लेना आसानी से स्वीकार्य नहीं होता। 48 घंटे की हिरासत का समय उनके सोचने के लिए पर्याप्त था। यह अधिक एक रणनीतिक पलटी लगती है ताकि वे अपने साथियों और संगठन को बचा सकें। कैरवन पत्रिका में असीमानंद के इन कबूलनामों को प्रकाशित किया गया, जिससे तहलका मच गया। बाद में असीमानंद ने इस इंटरव्यू से भी पल्ला झाड़ लिया। मगर रिपोर्टर और संपादक अपने दावों पर डटे रहे और उन्होंने इंटरव्यू के ऑडियो टेप भी जारी किए। मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में हाल में जो फ़ैसला आया, उसमें मुस्लिम आरोपियों को बरी किया गया और सरकार ने तुरंत इसके खिलाफ़ अपील दायर की। वहीं नांदेड़ विस्फोट मामले में जब आरोपी बरी हुए, तब दक्षिणपंथी खेमे में उत्सव का माहौल था, लेकिन सरकार की ओर से अपील की कोई बात नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि मालेगांव फ़ैसले से ठीक पहले संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, जिससे उन्होंने आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया। वह सुविधानुसार यह भूल गए कि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, राजीव गांधी की हत्यारिन धनु जैसे लोग भी हिंदू ही थे। लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।

देव भूमि से 'रुद्र' क्यों नाराज

शिव यानि कल्याण, शिव यानि संहार, सृष्टि के कल्याण का दायित्व शिव का है और संहार भी शिव के हाथों में है। यह तो मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्राकृति और जीवन में संतुलन बनाए रखे लेकिन दुर्भाग्य से उसने शिव को तीसरा नेत्र खोलने पर विवश कर दिया है। प्राकृतिक आपदाएं शाश्वत सत्य हैं। इंसानी सभ्यता की शुरूआत के साथ ही इनका भी इतिहास रहा है। यह तब भी कहर ढाती थी और आज भी कहर बरपा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इसके प्रकोप का शिकार जल्दी-जल्दी नहीं होना पड़ता था। उसमें एक लंबा अंतराल होता था। अब आए दिन प्राकृतिक आपदाओं की विभिषिका का इंसान को सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में बादल फटने से हुई भारी तबाही इसी की एक बानगी है। पलभर में ही खीर गंगा नदी में आए सैलाब से गांव, मकान, होटल सब कुछ जमींदोज हो गया। कितनों की मौत हुई और कितने ही लापता हुए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सब कुछ मलबे में दबा हुआ है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आपदाओं के चलते स्थिति बहुत खराब है। कुदरत के कहर ने आपदा से निपटने की राज्य की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सटीक पूर्वानुमान और आपदा के दौरान त्वरित संचार ही जीवन बचाता है लेकिन सड़कों के जगह-जगह से टूट जाने के कारण एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन को भी बचाव टीमें पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। ऊपर से बारिश ने भी कहर मचाया हुआ है। उत्तराखंड में 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की चमोली हिमस्खलन त्रासदी और 2023 के जोशीमठ जैसी घटनाएं बार-बार हमें चेतावनी देती रहीं कि कुछ कीजिए। पारिस्थितिकी संतुलन गंभीर रूप से बाधित हो चुका है लेकिन न सरकारों ने और न ही मनुष्य ने इस ओर ध्यान दिया। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से ही संवेदनशील है। इसकी कई वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरकाशी में आई आपदा का पैटर्न केदारनाथ में आई जलप्रलय की तरह ही था। दोनों घटनाओं की वजह भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ का हिमालय से टकराना रहा है जिससे बादल फटने की घटना ने विकराल रूप धारण कर लिया। इन परिस्थितियों के लिए कुछ तो दैवीय आपदा जिम्मेदार है और कुछ आपदाओं से होने वाले नुकसान के पीछे बहुत कुछ जीवन जीने की बदलती शैली, विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, अवैध खनन, बहुमंजिली इमारतों के विस्तार जैसे कारण भी जिम्मेदार है।

अगर देखें तो मानव की सुख-सुविधाओं के लिए पहाड़ को छलनी करने का परिणाम है कि पूर्व में यदा-कदा होने वाली आपदाएं अब आए दिन घट रही हैं। प्रत्येक वर्षा ऋतु में पहाड़ क्षेत्र में जाने का भय बना रहता है। जहां-तहां प्रकृति का तांडव दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पिछले सौ साल में पचास से ज्यादा विनाशकारी भूस्खलन आए है। प्राकृतिक आपदा कहर तो बरपाती है, साथ ही उस क्षेत्र का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। भूस्खलन, बाढ़ आदि के कारण कई तरह की रुकावटें आती हैं जिससे उस क्षेत्र के पूरे जन-जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में निर्माण कार्यों पर बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

खनन, नदी, घाटियों के कुछ किनारे कुछ निश्चित सीमा तक निर्माण कार्य रोकने, वनीकरण को बढ़ावा देने, कृषि की समुचित प्रणाली, वनस्पतियों की सुरक्षा, बड़ी विकास परियोजना की समीक्षा पर काफी गंभीरता बरती जानी जरूरी है। समय-समय पर आ रही दैवीय आपदाओं के कहर और विकास के नाम पर अति दोहन के बावजूद राज्य का सरकारी तंत्र आपदा प्रबंधन को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नदियों ने अपना रुख बदला तो लोगों ने मकान बना लिए। पहाड़ खोद-खोद कर होटल और होम स्टे बना दिए। पहाड़ों से आने वाला पानी कब अपना रास्ता बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता। चार धाम यात्रा मार्ग पर व्यापक निर्माणक गतिविधियों के चलते और हाईडल परियोजनाओं के चलते भी पहाड़ खोखले हुए। धराली आपदा भी इसलिए?हुई क्योंकि खीर गंगा में आई बाढ़ ने अपना पुराना रास्ता खोज लिया। हर आपदा के बाद अक्सर लोग कहने लगते हैं कि रुद्र देवभूमि उत्तराखंड से नाराज है। या भागीरथी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है लेकिन यह कोई सोच नहीं रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। महानगरों के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पहाड़ों में सड़कों और बांधों के निर्माण की योजनाएं बनाते समय यह कोई नहीं सोचता कि पहाड़ के विनाश का खाका खींच रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के वीडियो देखकर मनुष्य को अपने अस्तित्व का अहसास हो गया होगा। दैवीय आपदाओं को बेशक रोका नहीं जा सकता लेकिन स्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यद्यपि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक राहत कार्यों पर खुद नजर रख रहे हैं। प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। देशवासी भी व्यथित है। उत्तराखंड की मदद करने के लिए देशवासी भी तैयार हैं लेकिन मनुष्य को भी प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति अपने आप में एक विज्ञान है। यह विशिष्ट रूप से खुद को सुव्यवस्थित और सुसंगठित रखती है। इसके सभी अवयव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। हाल में हम सब ने लोभ के चलते प्रकृति में विकार पैदा कर दिया। इसके सभी अंगों के बीच तारतम्यता और संतुलन को गड़बड़ा दिया है। साल दर साल हम प्रकृति का विनाश करते आ रहे हैं। नदी के किनारे निर्माण करकर उसके स्वच्छंद फैलाव को सिकोड़ दिया। वनों को उजाड़ दिया। आबोहवा को बिगाड़ दिया। ऐसा करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि प्रकृति की सत्ता सबसे ताकतवर है। उसकी लाठी में बहुत जान है। इसके प्यार की लाठी सहारा बन जाती है और क्रोध की लाठी जान ले लेती है। लिहाजा प्रकृति के नैसर्गिक रूप पुनर्धारण के रास्ते में जो कोई भी आता है, बह जाता है, भस्म हो जाता है और उड़ जाता है।

बढ़ती उम्र में कुछ भूलना स्वाभाविक है

अरे भाई, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। यह वाक्य हम सभी ने कभी न कभी किसी बुजुर्ग के मुंह से जरूर सुना होगा-या खुद कहा भी होगा। कभी किसी का नाम याद नहीं आता, तो कभी कोई जरूरी बात जो अभी-अभी सोच रखी थी, वह मस्तिष्क से निकल जाती है। कई बार हम चेहरा तो पहचान लेते हैं लेकिन नाम जबान पर नहीं आता। यह सब कुछ बढ़ती उम्र के साथ सामान्य रूप से होता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने की एक सहज प्रक्रिया है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करते हुए समझदारी से निपटना जरूरी है। याददाश्त का कमजोर होना शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया। भगवान ने हमारे शरीर और मस्तिष्क को एक सीमित जीवन-चक्र के साथ बनाया है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कुछ ग्रंथियां और कोशिकाएं धीमी गति से काम करने लगती हैं। इनमें वे कोशिकाएं भी आती हैं जो याददाश्त से जुड़ी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मस्तिष्क की क्षमताएं पूरी तरह खत्म नहीं होतीं। वे केवल थोड़ी मंद हो जाती हैं। अगर हम मस्तिष्क की सही एक्सरसाइज करते रहें, तो इस मंदता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पुराने जमाने में हम बहुत कुछ याद रखते थे–जैसे रिश्तेदारों के पते, टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, जरूरी कामों की तिथियां, आदि। लेकिन आज की तकनीक-प्रधान जीवनशैली ने हमारे मस्तिष्क को 'आलसी' बना दिया है। फोन की डायरेक्टरी, रिमाइंडर, वॉयस नोट्स और गूगल की आदत ने हमें स्मरणशक्ति के अभ्यास से दूर कर दिया है। लिखने की आदत भी लगभग समाप्त हो हो गई है। पहले जब कुछ याद रखना होता था, तो उसे कई बार लिखना पड़ता था–स्कूल में कविता याद करने का सबसे आसान तरीका था। 10 बार लिखो, 10 बार पढ़ो। इससे स्मृति गहरी होती थी। अब हम उसे मोबाइल में एक नोट के रूप में सहेज लेते हैं और कई बार तो दोबारा देखना भी भूल जाते हैं। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने के लिए भी नियमित अभ्यास जरूरी है। यह अभ्यास केवल पहेलियां हल करने या शतरंज खेलने तक सीमित नहीं है। कुछ आसान लेकिन नियमित आदतें आपकी याददाश्त को बेहतर बना सकती हैं हर दिन अखबार पढ़ना और मुख्य समाचारों को संक्षेप में मन में दोहराना। जो बातें करनी है, उन्हें पहले मन ही मन क्रम से दोहराना। महत्वपूर्ण कार्यों की सूची डायरी में स्वयं लिखना, न कि केवल मोबाइल पर टाइप करना। किसी कहानी, फिल्म या यात्रा के बारे में याद कर दूसरों को सुनाना। यह स्मरण का अच्छा अभ्यास है। नए शौक अपनाना-जैसे संगीत, बागवानी, पेंटिंग, भाषा सीखना-मस्तिष्क को नई चुनौतियां देता है। तकनीक का उपयोग करें, लेकिन आत्मनिर्भरता भी बनाए रखें। आज कई लोग फोन या डायरी में जरूरी नोट्स रखने लगे हैं-यह कोई गलत आदत नहीं है। बल्कि यह एक समझदारी भरी आदत है। मेरे कुछ मित्र हर मीटिंग, हर फोन कॉल के बाद तुरंत अपनी पॉकेट डायरी में संक्षेप में वह बात लिख लेते है, जिससे उन्हें दोबारा याद करने में परेशानी न हो। यह आदत उनके आत्मविश्वास को भी बनाए रखती है। कुछ लोग याददाश्त की समस्या को लेकर डॉक्टर से परामर्श करते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पँचशील एन्क्ले. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

आधुनिक तकनीक के साथ हरियाणा और इजरायल मिलकर करेंगे काम - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनुसंधान, स्वास्थ्य, कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत सिंचाई प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमता, वेस्ट वाटर सहित अन्य क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से हरियाणा और इजराइल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर चण्डीगढ़ में भारत में इज़राइल के राजदूत रूवेन अज़ार ने शिष्टाचार मुलाकात कर आपसी सहयोग के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार, ओवरसीज प्लेसमेंट अधिक काम करने पर बल दिया गया। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तहत ओवरसीज प्लेसमेंट के माध्यम से अब तक 180 से अधिक युवा इजराइल में नौकरी कर रहे है। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इजराइल से पांच हजार नर्सों

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भारत में इज़राइल के राजदूत रूवेन अज़ार ने की शिष्टाचार मुलाकात
अनुसंधान, स्वास्थ्य, कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत सिंचाई प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमता, वेस्ट वाटर अन्य विषयों पर हुई चर्चा

को नौकरी देने की मांग देशभर में आई है। जिसमे हरियाणा और भागीदारी बढ़ाना चाह रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेंटर स्थापित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ताकि युवाओं को आधुनिक एआई कौशल में प्रशिक्षण देना और राज्य में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य इजराइल के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना चाहता है। हरियाणा में वेस्ट वाटर को सिंचाई में प्रयोग करने व पानी को कृषि योग्य एवं पीने योग्य बनाने के लिए इजराइल के साथ नई तकनीक पर कार्य करेंगे।

ताकि वेस्ट वाटर का उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने, दूसरे देशों से रिश्तों को और मजबूत करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेशों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले और निर्यात को दोगुना बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। इस दौरान पर मुख्यमंत्री ने इज़राइल के राजदूत रूवेन अज़ार को गीता की एक प्रति भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, हरियाणा विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार और विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार श्री पवन चौधरी उपस्थित रहे।

फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम 2025-.26 के तहत मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

पानीपत।

उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025.26 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के प्रोत्साहन हेतु सीआरएम स्कीम के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी जायेगी। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणा डॉटजीओवीडॉटइन) पर 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा0 आत्मा राम गोदारा ने बताया कि व्यक्तिगत लाभार्थी की श्रेणी में आवेदन करने के लिए किसान के नाम रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आर.सी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एवं बैंक खाता की आवश्यकता होगी। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत वर्तमान रबी 2025 और खरीफ सीजन 2024 होना अनिवार्य है।

एक किसान 04 मशीनों के लिये आवेदन कर सकता है हालांकि सबसीडी केवल एक मशीन पर ही दी जायेगी अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जिन किसानों ने पिछले 3 वर्षों में जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

उन्होंने बताया कि यदि इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थी का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। इस स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए सारी प्रक्रिया का संचालन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन उपायुक्त, पानीपत हैं। अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा सहायक कृषि अभियन्ता, पानीपत के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

उभरते भारत की सुरक्षा को और मजबूती: सीआईसीएफ कर्मियों की अधिकृत संख्या बढ़कर हुई 2.2 लाख

चंडीगढ़ ।

औद्योगिक सुरक्षा को और मज़बूती देने तथा देश के आर्थिक विकास को सुरक्षित आधार देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अधिकृत संख्या को 1,62,000 से बढ़ाकर 2,20,000 करने की मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय भारत की सुरक्षा नीतियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो औद्योगिक सुरक्षा को और मजबूत करने तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में मदद करेगा। पंजाब हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट के यूनिट कमांडर श्री ललित पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है और इसे सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। इस विस्तार से सीआईसीएफ की तैनाती कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होगी, जिनमें विमानन क्षेत्र, बंदरगाह, थर्मल पावर प्लांट्स, परमाणु प्रतिष्ठान, जल विद्युत संयंत्र, और जम्मू-कश्मीर स्थित जेल जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वामपंथी उग्रवाद में कमी के

अगले 5 वर्षों तक हर साल भर्ती होंगे 14,000 जवान

साथ नए औद्योगिक केंद्रों का उभरना संभव है, जिसके लिए सीआईसीएफ की उपस्थिति को और मजबूती से बढ़ाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सीआईसीएफमें तैनात कर्मियों की संख्या में विस्तार किया जा रहा है।

वर्ष 2024 में 13,230 नए कर्मियों की भर्ती की गई और 2025 में 24,098 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

अगले पाँच वर्षों में हर साल लगभग 14,000 नए जवान सीआईसीएफ में शामिल किए जाएंगे। जो बल को युवा ऊर्जा प्रदान करेंगे और इसे आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम बनाएंगे। इन भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसे सीआईसीएफ की उन नीतियों का समर्थन प्राप्त है जो महिलाओं को हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि बल की ताकत में यह इज़ाफा एक नई बटालियन के गठन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जो आंतरिक सुरक्षा, आपात तैनाती जैसी ज़रूरतों में अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, पिछले साल सीआईसीएफ ने अपनी सुरक्षा विंग के तहत सात नई इकाइयां शुरु की हैं, जिनमें संसद भवन परिसर, अयोध्या एयरपोर्ट, हजारीबाग में स्थित NTPC की कोयला खदान परियोजना, पुणे का सीआईसीएफ-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, बक्सर और एटा के ताप विद्युत संयंत्र और मंडी की ब्यास सतलुज लिंक परियोजना शामिल हैं। साथ ही, संसद भवन और एटा की परियोजना में अग्निशमन की दो नई इकाइयां भी शामिल की गई हैं।

श्री पवार ने बताया कि यह विस्तार न केवल भारत के बढ़ते औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के साथ मेल खाता है, बल्कि यह देश की प्रमुख राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा में सीआईसीएफ की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। यह विस्तार बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप सीआईसीएफकी क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि यह बल भारत के तेज़ी से हो रहे विकास की गति के अनुरूप एक मज़बूत और सतर्क सुरक्षा इकाई बना रहे।

सेवा का अधिकार आयोग ने झज्जर नगर निकाय विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध की कार्रवाई

चंडीगढ़ ।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक शिकायत के निराकरण में नगर निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। आयोग ने एक अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया है, दूसरे के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है तथा एक अन्य को भविष्य के लिए परामर्श (एडवाइजरी) जारी की है। आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया आयोग ने शिकायत में पाया कि संबंधित जूनियर इंजीनियर (नगर निकाय विभाग) ने यह गलत जानकारी दी कि संबंधित स्ट्रीट लाइट मरम्मत योग्य नहीं है, जबकि बाद में उसी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कर दी गई। यह स्पष्ट संकेत है कि मरम्मत पूर्व में भी संभव थी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर की जा सकती थी। साथ ही, पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीर, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीर से मेल नहीं खाती। सेवा समय पर न देने और अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(ह) के तहत जूनियर इंजीनियर (नगर निकाय विभाग) पर 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है। यह राशि अगस्त माह के वेतन से काटकर राज्य कोष में जमा की जाएगी। जिला नगर आयुक्त, झज्जर को 10 सितंबर तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। इसी मामले में संबंधित प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण-कम-म्यूनिसिपल इंजीनियर (नगर निकाय विभाग) ने भी सेवा न मिलने के बावजूद केवल इस आधार पर अपील खारिज कर दी कि शिकायतकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह रुख सेवा का समाधान करने के दायित्व से बचने का प्रयास है, जबकि अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि अपील का निर्णय तथ्यों के आधार पर किया जाए। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(ख) के अंतर्गत राज्य सरकार को उनके विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। नगर निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव को 30 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त अवधि में झज्जर जिले में जिला नगर आयुक्त का पद रिक्त था और कार्य लिंक अधिकारी द्वारा किया जा रहा था। आयोग ने यह अवलोकन किया कि लिंक अधिकारी द्वारा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित अधिकारी अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ यह कार्यभार संभाल रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस मामले में नरमी बरतते हुए उन्हें भविष्य के लिए परामर्श जारी किया है कि वे लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करते समय भी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। यह परामर्श एकतरफा रूप से जारी किया गया है और संबंधित अधिकारी को आयोग के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है।

हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़े हरियाणा के कदम

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा ने हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना के तहत दो लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के सौर ऊर्जा से जगमगाने का भी लक्ष्य है। कुल 122 मेगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक के दौरान दी गई। बैठक में योजना की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा ने केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है बल्कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह हर परिवार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंचे। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर (आरटीएस) स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य की बिजली वितरण

वित्त वर्ष 2026-27 तक लगेंगे दो लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र
दिसंबर तक सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे सभी सरकारी भवन
कैथल जिले का बालू बना प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम

कंपनियां आरटीएस स्थापना में तेजी लाने के लिए विशेष बूस्टर योजनाएँ लाने के लिए काम कर रही हैं। इन संयुक्त प्रोत्साहनों से मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग को बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी। बैठक में बताया गया कि कैथल जिले का बालू गाँव प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम बन गया है, जबकि करनाल और कुरुक्षेत्र में चयन प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि आदर्श सौर ग्राम (एमएसवी) कार्यक्रम के तहत हर जिले में एक गाँव को सौर ऊर्जा से संचालित आदर्श समुदाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल के तहत 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव 1 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के पात्र हैं। इन आदर्श गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, घरेलू प्रकाश व्यवस्था, सौर-आधारित जल प्रणालियां और सौर पंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे एक आत्मनिर्भर, 24X7 स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है। गौरतलब है कि रूफटॉप सोलर को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार द्वारा दोहरी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता संयंत्र की स्वीकृति से 15 दिन के अन्दर उपभोक्ता के बैंक खाते सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार भी 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर एक लाख अंत्योदय परिवारों को राज्य वित्तीय सहायता (एसएफए) प्रदान कर रही है। इस दोहरी सब्सिडी से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्थापना की प्रारंभिक लागत काफी कम हो जाती है। नागरिक सहायता बढ़ाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, प्रदेश के बिजली निगमों ने एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और उप-मंडलों में 280 से अधिक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं। क्षमता निर्माण पर भी अधिक ध्यान दिया गया है, जिसमें एनपीटीआई और एनआईईएसबीयूडी द्वारा संचालित विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से 703 डिस्कॉम अधिकारियों और विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

संसद : ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन पूरा होने की कोई समय-सीमा तय नहीं; केंद्र में 2016 से 4.8 लाख लंबित पद भरे गए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना के पूरा होने की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की जा सकती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के सवाल के लिखित उत्तर में दी। रेल मंत्री ने कहा कि किसी भी रेलवे परियोजना की प्रगति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे राज्य सरकार द्वारा तेजी से भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से पर्यावरण मंजूरी, राज्य सरकार द्वारा लागत साझेदारी की राशि का भुगतान, परियोजना की प्राथमिकता, आवश्यक तकनीकी स्वीकृतियां, भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां आदि।

हिमालय की कठिन भौगोलिक स्थिति है चुनौती

वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और बेहद कठिन हिमालयी भूभाग से होकर गुजरती है। इसका उद्देश्य चारधाम और गढ़वाल क्षेत्र को बेहतर रेल संपर्क देना है। यह लाइन देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों से होकर गुजरेगी।

अभी तक 199 किलोमीटर सुरंग का निर्माण पूरा

परियोजना में कुल 213 किलोमीटर सुरंग निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से 199 किलोमीटर सुरंग और 8 अडिट (सहायक मार्ग) बनकर तैयार हो चुके है। पहली बार भारतीय रेलवे ने टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल हिमालयी क्षेत्र में किया है। 14.8 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी सुरंग (टी-8) को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

चुनौतियों के बावजूद काम जारी

रेल मंत्री ने बताया कि सुरंग निर्माण कार्य पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक तकनीकों से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चारधाम प्रोजेक्ट का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को रेलवे से जोड़ेगा।

2016 से अब तक 4.8 लाख पद भरे गए- जितेंद्र सिंह

केंद्र सरकार ने बताया है कि वर्ष 2016 से अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में आरक्षित वर्गों के 4.8 लाख बैकलॉग पदों को भरा जा चुका है। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

बैकलॉग की पहचान के लिए समिति गठित करने के निर्देश

मंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए गए है कि वे इन-हाउस समिति बनाएं, जो बैकलॉग पदों की पहचान करे, कारणों की जांच करे और उन्हें दूर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। साथ ही, प्रत्येक विभाग में उप सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी को लायजन ऑफिसर नियुक्त करने और विशेष आरक्षण सेल बनाने के निर्देश भी दिए गए है।

आरक्षण की स्थिति और अनुपालन

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत, एससी को 15 प्रतिशत और एसटी को 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। प्रमोशन में एससी को 15 और एसटी को 7.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।

ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया- राहुल

स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर दावा- महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम, कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा

नई दिल्ली।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया. राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कहा है. आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को काफी गंभीर भी बताया है. आयोग ने कहा कि इन आरोपों को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई. एग्जिट पोल कुछ और नतीजे कुछ और थे. महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर थे. चुनाव आयोग इन लोगों को क्यों बचा रहा है. फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही थी. चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है. चुनाव आयोग वोटिंग के इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता. राहुल गांधी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों ने वोट चोरी की आशंका को मजबूत किया क्योंकि पांच महीने में पांच सालों से ज्यादा वोटर जोड़े गए. पांच बजे के बाद बड़ी संख्या में मतदान किया गया. इसको लेकर हमनें चुनाव आयोग के सामने बात रखी लेकिन चुनाव आयोग हमें डिजिटल वोटरलिस्ट देने से इंकार करता है. इसके बाद हमारी टीम ने छह महीने तक कागजातों को खंगाला उसके बाद हमने ये सबूत सामने लाए हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमारे आंतरिक सर्वे में कर्नाटक में हम 16 सीटें जीत रहे थे लेकिन हकीकत में केवल 9 सीटें जीती. जब हमने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर छानबीन की तो पता चला केवल एक विधानसभा सीट महादेवपुरा के भारी अंतर से बीजेपी ने लोकसभा सीट जीत ली. इस विधानसभा सीट पर एक लाख फर्जी वोटर बनवाए गए.

हलफनामा दें, गलत निकला तो लेंगे कानूनी एक्शन- ईसी

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपात्र मतदाताओं के जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार 1 से 3 बजे तक मिलने का समय भी दिया है. सीईओ ने राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे मतदाता सूची में शामिल या हटाए गए व्यक्तियों के नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर के साथ एक हलफनामा जमा करें ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके. हलफनामे में यह भी घोषणा करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है, और गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव परिणामों को केवल उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है.

हमारी नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही डबल इंजन सरकार : ममता

बंगाल। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की भाजपा की मांग के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को डबल इंजन वाली सरकार पर राज्य के लोगों की नागरिकता छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। झारग्राम में जनता को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि मैं सोच रही हूं, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? मुझे उम्मीद है कि हमारी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कृपया हमें इससे वंचित न करें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डबल इंजन वाली सरकार नागरिकों को रोहिंग्या बताकर उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बार-बार अदालत जाने के लिए भाजपा की भी आलोचना की। बनर्जी ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार हमारी नागरिकता छीनने, हमें रोहिंग्या कहकर हिरासत में लेने और हमें वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है। भाजपा हमेशा अदालत जाती है। मेरे पास 1912 का एक दस रुपये का नोट है, और वह बंगाली में लिखा है। फिर भी वे दावा करते हैं कि बंगाली भाषा है ही नहीं। इससे पहले, भाजपा सांसद और बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वे अवैध वोटों की मदद से जीत जाएँगी, तो यह उनकी गलतफहमी है। भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने एएनआई से कहा कि उन्हें विरोध करने दीजिए। ममता बनर्जी की मांग है कि मरने वालों के नाम क्यों हटाए जाएं। अगर उन्हें लगता है कि बांग्लादेशियों, जिहादियों, रोहिंग्याओं, अवैध प्रवासियों और अवैध मतदाताओं की मदद से वह चौथी बार सत्ता में आ सकती हैं, तो उनकी यह गलतफहमी है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री की आपत्तियाँ संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की जनता एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह के हमले को कैसे बर्दाश्त करेगी? ममता बनर्जी को जो भी कहना है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर बताना चाहिए... यह सरकार इस बार जाएगी। एक दिन पहले, ममता बनर्जी ने झारग्राम में एक विरोध मार्च निकाला और भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।

सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी- 3 की मौत, 5 गंभीर

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह 10:30 बजे सीआरपीएफ जवानों को लेकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक, 5 जवानों की हालत गंभीर है। सीआरपीएफ के अफसरों के अनुसार, गाड़ी जवानों के एक दल को ले जा रहा था, जो सड़क से फिसलकर खड़ी ढलान से नीचे खाई में जा गिरा। 3 शव घटनास्थल से बरामद किए जा चुके है, जबकि कई घायल जवानों को गंभीर हालत में रेस्क्यू कर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया. उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए हैं. डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा, कंडवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के एक वाहन के एक्सीडेंट की खबर सुनकर दुखी हूं. वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे. बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है. स्थानीय लोग खुद से ही मदद के लिए आगे आए हैं. हर संभव सहायता की जा रही है.

अमेरिका की धुन पर नाच रहे हैं मोदी -तेजस्वी

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। यादव ने इस मुद्दे पर मोदी की चुप्पी की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री कमजोर हो गए हैं। उन्होंने उन पर अमेरिका के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए, राजद नेता ने कहा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस देश में सरकार कैसे काम कर रही है। ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया। ट्रंप 28 बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्धविराम कराया। प्रधानमंत्री ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मोदी पर तंज कसते हुए राजद नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी तक यह नहीं कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं। 50 प्रतिशत टैरिफ से देश को बहुत नुकसान होगा, और कोई इस पर बोल नहीं रहा है। सब चुप है। ये लोग देश को नुकसान पहुँचाएँगे और फिर बिहार जाकर कहेंगे, देखो, हम विश्वगुरु बन गए हैं। इसके अलावा, यादव ने कथित डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबरों के संबंध में चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर कहा कि उन्हें आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि अगर दो ईपीआईसी नंबर जारी किए जाते हैं, तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी। यादव ने कहा कि मुझे चुनाव आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है। मुझे पटना ज़िला निर्वाचन क्षेत्र से एक नोटिस मिला है, और मैं उसका उचित जवाब दूँगा। मुद्दा यह है कि अगर दो ईपीआईसी नंबर जारी किए जाते हैं, तो इसमें किसकी गलती है? मेरा मतलब है, वे गलती करते हैं, और फिर मुझसे स्पष्टीकरण मांगते हैं? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? मैंने हमेशा एक ही जगह से वोट दिया है। मेरे जवाब का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा।

मोदी जी 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56 फीसदी टैरिफ लगाएंगे - असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका की तरफ से 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का और टैरिफ लगा दिया है, जिससे यह बढ़कर 50 फीसदी हो गया है, क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था. यह कूटनीति नहीं, बल्कि उस मसखरे की धौंस है, जो साफ़ तौर पर नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है. ओवैसी ने लिखा कि ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएंगे.. यह सप्लाई चेन को बाधित करेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकेगा और नौकरियों पर भारी असर डालेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह क्यों होगी? ओवैसी ने सवाल करते हुए पूछा कि अब वे भाजपाई बाहुबली कहां हैं? पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56 फीसदी टैरिफ लगाएंगे. ट्रंप 50 फीसदी पर रुक गए, शायद वे हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं? क्या अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बेचना आपके दोस्तों के अरबपतियों के खजाने भरने के लायक था?

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, सोनिया और राहुल गांधी भी आरोपी

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर ईडी से कुछ स्पष्टीकरण मांगे है। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा निजी कंपनी यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब शुक्रवार को इस बात पर निर्णय सुना सकते हैं कि क्या ईडी द्वारा मनी लॉड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए। अदालत को इस मामले में 29 जुलाई को फैसला सुनाना था, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने इसे सात व आठ अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए टाल दिया था। 14 जुलाई को अदालत ने ईडी और आरोपित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी थी कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करीब दो हजार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को महज 90 करोड़ रुपये के ऋण के एवज में यंग इंडियन द्वारा धोखाधड़ी से अधिगृहीत किया गया। ईडी का दावा है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और इसे एजेएल की संपत्तियों को अवैध तरीके से हासिल करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था।

मोदी सरकार की विदेश नीति फेल : मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता बताया। खरगे ने कहा कि ट्रंप का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत की कूटनीति कमजोर और भ्रमित नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और अब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं।

बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए भारत से आने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त 25फीसदी शुल्क लगा दिया। पहले से ही 25फीसदी टैरिफ लागू था, जिससे अब कुल शुल्क 50 फीसदी हो गया है। यह आदेश 7 अगस्त से लागू हो गया है।

पीएम मोदी पर किया कटाक्ष

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आप अमेरिका से व्यापार समझौता नहीं कर पाए। आपके मंत्री महीनों से बातचीत की बात कर रहे थे, कुछ तो वाशिंगटन में डेरा डाले बैठे थे। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और अब यह बड़ा झटका आया है, लेकिन आप चुप हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आप इस विदेश नीति की विफलता का जिम्मा 70 साल की कांग्रेस सरकारों पर भी नहीं डाल सकते।

पीएम मोदी के चुप्पी पर उठाए सवाल

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छह महीने से ज्यादा वक्त होने के बावजूद अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ट्रंप अब भारत को धमका रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप हैं। खरगे ने कहा कि पीएम मोदी ने उस समय भी कुछ नहीं कहा जब 2024 में ट्रंप ने BRICS को मृत कहा और 100फीसदी टैरिफ की धमकी दी।

आर्थिक असर को लेकर जताई चिंता

इसके साथ ही खरगे ने अमेरिका के टैरिफ नीति पर आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 7.51 लाख करोड़ (2024) का है। 50 फीसदी टैरिफ से भारत पर लगभग 3.75 लाख करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कृषि, एमएसएमई, डेयरी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयाँ, पेट्रोलियम और कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

लगातार नौ दिन बढ़ा पांच मीटर जलस्तर, विश्वनाथ मंदिर द्वार से 12 सीढ़ी नीचे गंगा

वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को गंगा में उफान कम हुआ तो जलधारा सड़कों और गलियों से वापस घाटों की सीढ़ियों तक लौटने लगी है। गंगा बाबा विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार से 12 सीढ़ी नीचे हैं। वहां ललिता घाट और दीवारें पूरी तरह से पानी में डूबी है। नमो घाट गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। किसी भी पर्यटक या श्रद्धालुओं को आने-जाने नहीं दिया गया। राजघाट की सड़क पर लगा पानी पीछे हटकर वापस सीढ़ियों पर चला गया। घाटों पर मंदिरों के शिखर का कुछ हिस्सा दिखने लगा है। मणिकर्णिका घाट की ओर से आया पानी अब गली में आश्रम के गेट से थोड़ा पीछे हो गया है।

संभल में सीएम ने किया 660 करोड़ रुपये की 221 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण

संभल।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को संभल को 546.25 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 108 कार्यों का शिलान्यास और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी शामिल है। मुख्यमंत्री मुरादाबाद से हेलीकॉप्टर द्वारा संभल पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर गांव आनंदपुर स्थित नवीन पुलिस लाइन में उतरा, जहां से वह कार द्वारा जनसभा स्थल पहुंचे। सभा स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत कल्कि भगवान की तस्वीर भेंटकर किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवीन रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया। उनके आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे कार्यक्रम के दौरान मुस्तैद नजर आए। इससे एक दिन पहले मुरादाबाद में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश के हर जिले में एक माफिया होता था। अब माफिया जेलों में है या ऊपर पहुंच गए हैं। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने कहा कि हर मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय है। एक जिला एक उत्पाद योजना से हर जिला आत्मनिर्भर बन रहा है। सीएम ने कहा कि जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, उन्हें ही विकास से दिक्कत है। 2017 से पहले मुरादाबाद के उद्यमी परेशान थे। यहां के उत्पाद वैश्विक बाजार में दम तोड़ रहे थे। आज व्यापारियों को बेहतर कानून व्यवस्था और सरकार की पारदर्शी नीतियां मिलीं तो निर्यात 11000 करोड़ तक पहुंच गया है।

बुद्धि विहार स्थित संविधान साहित्य पार्क और हनुमान वाटिका देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की प्रशंसा की। कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन और विभिन्न परियोजनाओं से मुरादाबाद की तस्वीर बदल रही है।

संविधान पार्क को लेकर उन्होंने कहा कि छात्रों को वहां जरूर जाना चाहिए और बाबा साहेब के संविधान को नजदीक से जानना चाहिए। हनुमान वाटिका में पवन पुत्र के शौर्य व भक्ति से परिचय करना चाहिए।

हम दोनों भाई निर्णय लेने में सक्षम हैं

राज ठाकरे के साथ भविष्य पर बोले उद्धव ठाकरे

मुंबई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देगा है, यह फैसला सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवार की घोषणा के बाद करेगी। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि जगदीप धनखड़ ने अचानक पद क्यों छोड़ दिया।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने परिवार के राजनीतिक पुनर्मिलन और आगामी चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन के मद्देनजर चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों भाई एक-दूसरे के साथ गठबंधन पर फैसला लेने में सक्षम है और इंडिया ब्लॉक का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इस संबंध में कोई नियम और शर्तें नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट वोटर ट्रेल मशीनों का इस्तेमाल न करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), पुणे, नागपुर और नासिक आने वाले महीनों में होने वाले प्रमुख स्थानीय निकाय चुनावों में शामिल है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सर्वोच्च प्राथमिकता हैं वाली टिप्पणी पर निशाना साधा। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बीच यह टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020-21 में कृषि विधेयकों के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान किसानों की कोई परवाह नहीं की। किसानों के विरोध प्रदर्शन को याद करते हुए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया गया और कुछ की तो मौत भी हो गई। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा, जो किसान दिल्ली आना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। कुछ गरीब किसान मर गए। आपको तब किसान याद नहीं आए। अब आपको किसान याद आ रहे है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के झूठ अब उजागर हो रहे है। ठाकरे ने कहा कि अब हर कोई कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं। इसका मतलब है कि उनके पिता भूख हड़ताल पर थे और उन्हें दिल्ली आने की अनुमति नहीं थी। उन पर बंदूकें तान दी गईं। दीवारें खड़ी कर दी गईं और उन्हें नक्सली कहा गया। उनके सारे झूठ धीरे-धीरे, दिन-ब-दिन बेनकाब हो रहे है और उनका असली चेहरा सामने आ रहा है।